Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2026, E-Journal, Vol. I, Issue LIV (54), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभार्थियों की सामाजिक-आर्थिक विकास का अध्ययन

डॉ. विवेक कुमार पटेल* संजय कुमार पटेल**

***सह प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (वाणिज्य) प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शास. शहीद केदारनाथ महविद्यालय, मऊगंज (म.प्र.) भारत**
**** शोधार्थी, एम् फिल (वाणिज्य) प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शास. शहीद केदारनाथ महविद्यालय, मऊगंज (म.प्र.) भारत**

शोध सारांश – भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के परिवारों को सुरक्षित एवं सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है।प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक पात्र परिवार को सुरक्षित एवं पक्का आवास उपलब्ध कराना है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) अप्रैल 2016 से लागू है, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) वर्ष 2015 से संचालित है। दिसंबर 2025 तक PMAY-G के अंतर्गत 3.86 करोड़ से अधिक आवास स्वीकृत तथा लगभग 2.92 करोड़ आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। वहीं PMAY-U के अंतर्गत लगभग 1.73 करोड़ आवास स्वीकृत तथा 99 लाख से अधिक आवास पूर्ण किए गए हैं। अध्ययन में सामाजिक विकास के संकेतकों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरणकृतथा आर्थिक विकास के संकेतकोंकृजैसे आय, रोजगार, वित्तीय समावेशन एवं परिसंपत्ति सृजनकृका मूल्यांकन किया गया है। प्राथमिक आँकड़ों का संकलन लाभार्थियों के सर्वेक्षण द्वारा तथा द्वितीयक आँकड़ों का संकलन ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) तथा नीति आयोग की रिपोर्टों से किया गया है। साथ ही, योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों की भी पहचान करेगा तथा नीति-निर्माताओं के लिए उपयोगी सुझाव प्रस्तुत करेगा।

शब्द कुंजी – प्रधानमंत्री आवास योजना, सामाजिक-आर्थिक विकास, लाभार्थी, ग्रामीण विकास, जीवन स्तर, आर्थिक सशक्तिकरण।

प्रस्तावना – आवास मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा और मकानकृमें से एक है। सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण आवास न केवल व्यक्ति को आश्रय प्रदान करता है, बल्कि उसके स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सम्मान तथा आर्थिक विकास पर भी गहरा प्रभाव डालता है। भारत जैसे विकासशील देश में बड़ी संख्या में परिवार लंबे समय तक कच्चे एवं असुरक्षित मकानों में रहने को विवश रहे हैं।

इसी समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) प्रारंभ की। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक प्रत्येक पात्र परिवार को पक्का आवास उपलब्ध कराना था, जिसे आगे भी जारी रखा गया। योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के पात्र परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे सुरक्षित एवं सम्मानजनक आवास प्राप्त कर सकें। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) अप्रैल 2016 से लागू है, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) वर्ष 2015 से संचालित है। दिसंबर 2025 तक PMAY-G के अंतर्गत 3.86 करोड़ से अधिक आवास स्वीकृत तथा लगभग 2.92 करोड़ आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। वहीं PMAY-U के अंतर्गत लगभग 1.73 करोड़ आवास स्वीकृत तथा 99 लाख से अधिक आवास पूर्ण किए गए हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रभाव केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं है। इससे लाभार्थियों के स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, सामाजिक प्रतिष्ठा, रोजगार, आय तथा वित्तीय समावेशन में भी सुधार देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश का मऊगंज जिला सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में पात्र परिवारों को लाभ मिला है। इसके बावजूद यह जानना आवश्यक है कि योजना से लाभार्थियों की आय, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सामाजिक प्रतिष्ठा तथा जीवन स्तर में कितना परिवर्तन हुआ है। साथ ही, योजना के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं एवं चुनौतियों का भी अध्ययन आवश्यक है। इसी पृष्ठभूमि में प्रस्तुत अध्ययन 'प्रधानमंत्री आवास योजना' का लाभार्थियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर प्रभाव: यह अध्ययन लाभार्थियों के अनुभवों तथा प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों के आधार पर योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करेगा तथा नीति-निर्माताओं के लिए उपयोगी सुझाव प्रस्तुत करेगा। इस शोध से यह समझने में सहायता मिलेगी कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल आवास उपलब्ध कराने की योजना नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, आर्थिक सशक्तिकरण एवं समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य – इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभार्थियों की सामाजिक-आर्थिक विकास पर प्रभाव में विश्लेषण करना है। अध्ययन के माध्यम से यह जाना जाएगा कि योजना से लाभार्थियों की आय, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक प्रतिष्ठा, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन तथा जीवन स्तर में कितना सुधार हुआ है। साथ

ही, योजना के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं, लाभार्थियों की संतुष्टि तथा योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाएगा। अध्ययन के आधार पर ऐसी नीतिगत सिफारिशें प्रस्तुत की जाएँगी, जिनसे प्रधानमंत्री आवास योजना को और अधिक प्रभावी एवं लाभार्थी-केंद्रित बनाया जा सके।

1. प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभार्थियों की सामाजिक स्थिति पर प्रभाव का अध्ययन करना।
2. लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति पर योजना के प्रभाव का मूल्यांकन करना।
3. योजना के कारण आय, रोजगार एवं जीवन स्तर में हुए परिवर्तन का विश्लेषण करना।
4. शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर योजना के प्रभाव का अध्ययन करना।
5. लाभार्थियों के सामाजिक सम्मान एवं वित्तीय समावेशन में हुए परिवर्तन का मूल्यांकन करना।
6. योजना के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं एवं चुनौतियों की पहचान करना।
7. लाभार्थियों के संतुष्टि स्तर का अध्ययन करना।

साहित्य समीक्षा

1. योजना आयोग (2014) के अनुसार ग्रामीण आवास योजनाओं से निर्माण क्षेत्र में रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलती है।
2. रंगराजन (2014) के अनुसार आवास की उपलब्धता गरीबी उन्मूलन की प्रक्रिया को स्थायित्व प्रदान करती है। उन्होंने यह तर्क दिया कि बिना सुरक्षित आवास के गरीबी उन्मूलन की योजनाएँ अल्पकालिक सिद्ध होती हैं।
3. प्रो. आर. एन. शर्मा (2016) शर्मा ने पाया कि ग्रामीण आवास एक ऐसी परिसंपत्ति बन गया जिसने परिवारों को आर्थिक जोखिम लेने योग्य बनाया। पक्का मकान मिलने के बाद ग्रामीण परिवार कृषि निवेश, पशुपालन और लघु व्यवसाय में निवेश करने लगे, जिससे उनकी आय में दीर्घकालीन वृद्धि हुई।
4. दत्त एवं सुंदरम (2016) ने अपने अध्ययन में पाया कि PMAY-G के अंतर्गत निर्मित आवासों से ग्रामीण परिवारों की सामाजिक सुरक्षा एवं जीवन स्तर में सुधार हुआ है।
5. देसाई (2017) के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ने गांवों में आधारभूत संरचना के विकास को गति दी है।
6. मुखर्जी (2018) ने अपने शोध में बताया कि क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) ने शहरी मध्यम वर्ग को आवास ऋण प्राप्त करने में सहायता प्रदान की।
7. शुक्ला (2019) ने अपने अध्ययन में पाया कि च्ड।ल् के अंतर्गत महिला स्वामित्व से महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हुई है।
8. डॉ. मोहित जैन (2020) जैन के अनुसार PMAY-G से ग्रामीण परिवारों की जोखिम सहनशीलता बढ़ी, जिससे वे नई कृषि तकनीकें, बीज और उत्पादन विधियाँ अपनाने लगे। यह ग्रामीण आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण संकेत है।
9. यादव (2020) ने अपने शोध में यह पाया कि जिन गांवों में PMAY-G का प्रभावी क्रियान्वयन हुआ, वहां पलायन की प्रवृत्ति में आंशिक कमी देखी गई।

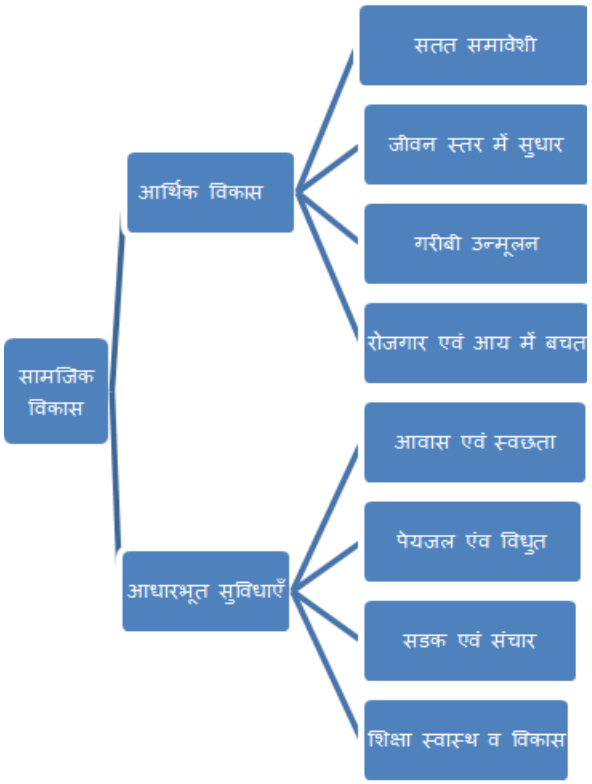
शोध परिकल्पना :

1. जिले के पात्र हितग्राहीयों तक आवास योजना प्राप्त हो रहा हैं।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उचित व्यक्ति को मुहैया कराया जा रहा हैं।
3. हितग्राहियों के आर्थिक व सामाजिक विकास में बढ़ावा
4. प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभार्थियों के सामाजिक-आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव है।

शोध विधि - शोधार्थी द्वारा इसका विश्लेषण कर सरणीयन के समंको के माध्यम से शोध क्षेत्र का समंक तैयार करने का अकादमिक प्रयास किया गया हैं। इसी आधार पर निम्न शोध विधि का प्रयोग किया जयेगा- और यह विधि दो प्रकार से हैं।

1 प्रथामिक समंक- प्रश्नावली एवं साक्षात्कार
2. द्वितियक समंक सरकारी रिपोर्ट, जनगणना, मंत्रालय की रिपोर्ट, शोध-पत्र, पुस्तकें

सामजिक आर्थिक विकास के मुख्य घटक



प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) विकास का प्रभाव- भारत योजना प्रारंभ 2015 (PMAY-U), 2016 (PMAY-G) का सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 2016 से 2025 तक देशभर में लगभग 3.9 करोड़ से अधिक ग्रामीण आवास स्वीकृत किए गए। इनमें से लगभग 3.3 करोड़ से अधिक आवास पूर्ण हो चुके हैं इससे कच्चे मकानों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई।

जैसे-

1. **ग्रामीण रोजगार में वृद्धि-**प्रत्येक आवास निर्माण से औसतन 90-100 मानव-दिवस का रोजगार सृजित होता है (मनरेगा के समन्वय

सहित)।
इससे करोड़ों मानव-दिवस का रोजगार उत्पन्न हुआ और स्थानीय मजदूरों को काम मिला।

2. गरीबी में कमी- पक्का घर मिलने से परिवारों का आवास पर होने वाला अतिरिक्त खर्च कम हुआ। बिजली, शौचालय, स्वच्छ पेयजल और एलपीजी जैसी सुविधाओं से जीवन स्तर में सुधार हुआ।

3. स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर प्रभाव- सुरक्षित आवास के कारण वर्षा, धुआँ और संक्रमण से होने वाली बीमारियों में कमी देखी गई।
बच्चों की शिक्षा के लिए बेहतर अध्ययन वातावरण उपलब्ध हुआ।

4. महिला सशक्तिकरण- अधिकांश घरों का स्वामित्व महिला मुखिया या संयुक्त नाम से दिया गया।
जिससे महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति मजबूत हुई।

सुझाव :

1. लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाया जाए।
2. निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की नियमित तकनीकी निगरानी सुनिश्चित की जाए।
3. सभी किस्तों का भुगतान समयबद्ध रूप से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किया जाए।
4. योजना को स्वरोजगार, कौशल विकास तथा आजीविका कार्यक्रमों से जोड़ा जाए ताकि आवास के साथ आर्थिक सशक्तिकरण भी सुनिश्चित हो सके।
5. आवास के साथ पेयजल, विद्युत, सड़क एवं डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं का समेकित विकास किया जाए।
6. महिला स्वामित्व एवं संयुक्त स्वामित्व को और अधिक प्रोत्साहित किया जाए।
7. योजना के क्रियान्वयन में सूचना प्रौद्योगिकी, जियो-टैगिंग एवं ऑनलाइन निगरानी प्रणाली को और मजबूत किया जाए।

निष्कर्ष - उपरोक्त अध्ययन से यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) ने लाभार्थियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। योजना के माध्यम से कच्चे एवं जर्जर आवासों में रहने वाले परिवारों को सुरक्षित एवं पक्के आवास उपलब्ध हुए, जिससे उनके जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार आया। देशभर में PMAY-G के अंतर्गत लगभग 2.92 करोड़ से अधिक आवास पूर्ण किए जा चुके हैं, जो ग्रामीण परिवारों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का संकेत है। अध्ययन से ज्ञात होता है कि पक्का आवास प्राप्त होने के बाद लाभार्थियों की सामाजिक प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास तथा सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि हुई है। स्वच्छ शौचालय, पेयजल, विद्युत एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता से स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की स्थिति में सुधार देखा गया। महिलाओं की भागीदारी एवं संपत्ति पर स्वामित्व बढ़ने से महिला सशक्तिकरण को भी बल मिला। आर्थिक दृष्टि से योजना ने लाभार्थियों को स्थायी संपत्ति प्रदान की है, जिससे आर्थिक सुरक्षा बढ़ी है। आवास निर्माण गतिविधियों ने रोजगार सृजन में भी योगदान दिया है तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की है। PMAY-G के अंतर्गत निर्माण कार्यों से करोड़ों मानव-दिवस रोजगार सृजित हुए हैं।

अत: यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल आवास निर्माण कार्यक्रम नहीं है,बल्कि सामाजिक समावेशन, गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण तथा सतत ग्रामीण विकास का प्रभावी माध्यम है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची:-

1. त्रिपाठी, ए.एन. (2013) - ग्रामीण बसावट एवं आवास संरचना, हिंदी ग्रंथ अकादमी।
2. सिंह, सुरेंद्र (2014) - ग्रामीण आवास योजनाएँ, अनमोल पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
3. शर्मा, रामकुमार (2015) - ग्रामीण आवास एवं विकास, रावत पब्लिकेशन।
4. जयपुर. चौधरी, महेंद्र (2016) - ग्रामीण जीवन और आवास, वाणी प्रकाशन।
5. भारत सरकार (2016), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) - संचालन मार्गदर्शिका, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
6. भारत सरकार (2016) - प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY-G) दिशा-निर्देश, ग्रामीण विकास मंत्रालय।
7. मिश्रा, ओमप्रकाश (2017) - भारत में ग्रामीण आवास, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली।
8. यादव, जगदीश (2018) - ग्रामीण गरीबी और आवास समस्या, राजकमल प्रकाशन।
9. PMAY-G लाभार्थी सूची और प्रदर्शन आँकड़े।
10. राज्य सरकारों द्वारा PMAY-G के क्रियान्वयन रिपोर्ट्स

****